सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-227
17/05/2017

स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बैंक टालमटोल नहीं करें :– मुख्यमंत्री

पटना, 17 मई 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 60वीं (प्लैटिनम जुबली) बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि सबसे पहले मैं बैठक में आये सभी लोगों का स्वागत करता हूँ तथा उन्हें बधाई देता हूँ। बिहार के पुनर्गठन के बाद की यह 60वीं राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक है। पिछले एक दशक में बैंकर्स समिति की अनेक बैठकों में शामिल होने का अवसर मिला है। 25 मई 2016 को आयोजित बैठक में भी मैं शामिल हुआ था। उन्होंने कहा कि जिन–जिन विषयों पर बैंकर्स समिति की बैठक होती है, उन सभी विषयों पर मैंने अपनी राय रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस वर्ष साख जमा अनुपात में गिरावट आयी है। वर्ष 2016–17 में साख जमा अनुपात 43.94 प्रतिशत रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की असीम संभावनायें हैं। बिहार के लोग बैंक खाता में पैसा जमा कराते हैं परन्तु अगर यहॉ के लोगों को विकास योजनाओं के लिये ऋण उपलब्ध नहीं होगा तो इससे विकास अवरूद्ध होगा। अभी यह मात्र 44 प्रतिशत तक गया है, जबकि बहुत सारे विकसित राज्यों में यह अनुपात 100 प्रतिशत से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वांगिण विकास के लिये पूरे मूल्क का विकास जरूरी है। आज देश में विकास के कुछ द्वीप बन गये हैं, यही कारण देश का विकास दर फलक्चुयेट करता है। आज देश का विकास दर कुछ राज्यों के विकास दर पर निर्धारित है। अगर देश के सभी भागों में एकरूपी विकास होगा तो देश का विकास दर हमेशा बढ़ता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के वरीय अधिकरारियों को कहा कि आप अपने से नीचे के स्तर के कार्यप्रणाली को जब तक नहीं सुधारेंगे, तब तक विकास संभव नहीं होगा। आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राशि के ट्रांसफर का उदाहरण देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिये दी गयी राशि बैंकों में महीनों तक पड़ी रह जाती है। अगर समय पर लोगों का पैसा नहीं मिला तो यह पूरी प्रणाली बेकार साबित हो जायेगी। प्रक्रिया का ससमय अनुपालन होना चाहिये। उन्होंने कहा कि समय से पैसे नहीं मिलने पर लोगों को तकलीफ होती है। बैंकों द्वारा ब्रांच खोले जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 1,640 नये ब्रांच खोलने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक मात्र 139 ब्रांच खोले गयें हैं, यह काफी कम है। बैंको की नीति है 5 हजार की आबादी पर ब्रांच खोलने की। आप बिहार के प्रत्येक ग्राम पंचायत में तो ब्रांच खोलिये। ग्राम पंचायतों की आबादी 10 हजार से ऊपर रहती है। उन्होंने कहा कि 1/6 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया है। वैसे ग्राम पंचायतों में पहले ब्रांच खोलिये अगर स्थान चाहिये तो बैंकों को हम स्थान उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने कहा कि लेन–देन की प्रक्रिया डिजिटली होनी है तो बैंकों को अपनी आधारभूत संरचनायें सुधारनी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिये लोगों के बीच रूपे कार्ड को लोकप्रिय बनाइये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को पेंशन भुगतान किया जाता है। 15.11.2000 के पूर्व सेवानिवृत होने वाले अभिवाजित बिहार के राज्य कर्मियों एवं 15.11.2000 के पूर्व एवं बाद में सेवानिवृत होने वाले पेंशनरों को अलग–अलग शीर्ष से भुगतान किया जाता है ताकि झारखण्ड से दायित्वों का बटवारा हो सके। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा

15.11.2000 के पूर्व एवं बाद में सेवानिवृत होने वाले पेंशनरों का भुगतान नव बिहार राज्य खाते में बुक किया जा रहा है। इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन मद में बैंक द्वारा अधिक भुगतान किया जा रहा है। महालेखाकार के आपत्ति के बाद बैंकों को राशि वसूल कर सरकार के खाते में जमा करना है, इसे इम्पलिमेंट कीजिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के जो युवा जितनी भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिये बैंकों द्वारा चलाई जा रही पूर्व की शिक्षा ऋण योजना पूरी तरह से प्रभावी नहीं था। उसमें इतना सारा प्रावधान है कि आम छात्रों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। उन्होंने कहा कि बिहार का उच्च शिक्षा में ग्रोश इनरॉलमेंट रेशियो मात्र 13.9 प्रतिशत है। हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, हम इसे 30 से 40 प्रतिशत पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण इच्छुक छात्र–छात्रायें 12वीं के आगे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। इसे देखते हुये स्टुटेंड क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गयी। सात निश्चय के तहत एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल के पॉच अवयव में से एक स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड है। उन्होंने कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण की मूल राशि एवं सूद पर सरकार ने पूरी गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड का जो आवेदन बैंकों को भेजा जा रहा है, उसे बैंकों द्वारा तुरंत स्वीकृत करना चाहिये। उन्होंने कहा कि जब कोई नई चीज की शुरूआत की जाती है तो उसमें कठिनाई आती है इसीलिये हमने यात्रा किया, सभी जगह जाकर देखा। आप भी इस योजना को प्रचारित कीजिये। कल राजभवन में आयोजित कुलपति–प्रतिकुलपतियों की बैठक में भी हमने सबसे आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने लड़कियों की शिक्षा का उदाहरण देते हुये कहा कि पहले मध्य विद्यालयों में पढ़ रही लड़कियों की संख्या काफी कम थी। लोग गरीबी के कारण लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते थे। हमने पोशाक योजना की शुरूआत की। इससे मध्य विद्यालयों में पढ़ रही लड़कियों की संख्या बढ़ गयी। उच्च विद्यालयों में लड़कियों के लिये साइकिल योजना की शुरूआत की गयी। इससे उच्च विद्यालयों में पढ़ रही लड़कियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुयी। इस वर्ष मैंट्रिक परीक्षा में लड़के–लड़कियों का अनुपात 49 प्रतिशत रहा है। अगर बिहार के लिंग अनुपात के नजरिये से देखियेगा तो लड़कियों की संख्या और बढ़ जायेगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह अगर स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पूरी तरह से लागू होगा तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में टालमटोल नहीं कीजिये। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की प्रवृति ऋण लेने की नहीं होती है। हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सरकार पूरी गारंटी देगी।

सुरक्षा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाना एक चुनौती है लेकिन प्रायः बैंकों द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि हम स्टेट इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्स का गठन करने जा रहे हैं। इसके दो बटालियन के गठन का निर्णय हो गया है। एक बटालियन बेगूसराय में और एक बटालियन डुमरांव में स्थापित रहेगा। इनके माध्यम से बैंकों को सुरक्षा देने में मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं नोटबंदी का समर्थक रहा हूँ, आप भी नोटबंदी पर आत्ममंथन कीजिये कि इसमें बैंकों की भूमिका क्या रही। उन्होंने कहा कि देश के विकास में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप लोग केवल नौकरी नहीं सेवा कीजिये। आज इस 60वीं बैठक में आप लोग संकल्प लीजिये कि देश के विकास एवं उन्नति में जो हमारी भूमिका है, उसे पूरी तरह निभायेंगे। सरकार आपकी पूरी मदद एवं सहयोग के लिये तैयार है। आपके तरफ से भी पूरा सहयोग होना चाहिये। उन्होंने कहा कि बैंकों का पूर्ण सहयोग जब मिल जायेगा बिहार का विकास दर और बढ़ जायेगा एवं स्थायी हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जी0एस0टी0 लागू होने के बाद बिहार और आगे बढ़ेगा। हम शुरू से जी0एस0टी0 के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि बिहार में सामाजिक सुधार के कार्य हुये हैं। शुरू में लोग कहते थे कि शराबबंदी के बाद सरकार की

आय में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी लागू होने के बाद भी सरकार के राजस्व आय में ज्यादा फर्क नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं को सशक्त करने के लिये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। बिहार में गठित स्वयं सहायता समूह का मॉडल देश में सबसे अच्छा है। स्वयं सहायता समूह का गठन पूरे बिहार में किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 6 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। हमारा लक्ष्य 10 लाख स्वयं सहायता समूह के गठन का है। उन्होंने कहा कि बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली मदद में काफी गैप है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराने में जो गैप है उसको समाप्त कीजिये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी की तरफ से अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह् भेंट किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री अब्दुलबारी सिद्दीकी, कृषि मंत्री श्री रामबिचार राय, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, नगर विकास एंव आवास मंत्री श्री महेश्वर हजारी, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त श्री रवि मित्तल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजीत सूद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि श्री बृजराज, नबार्ड के महाप्रबंधक श्री राम अवतार मिश्र सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं बैंकों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

******